



## 12 हजार से अधिक मरीजों ने घर बैठे लिया डॉक्टर से अपॉइंटमेंट

मीडिया ऑडीटर, भोपाल (एजेंसी)। आयुष्मान भारत नियममय हेल्पलाइन सेवा से अब तक 12 हजार से ज्यादा मरीजों ने घर बैठे डॉक्टरों से अपॉइंटमेंट लिया है। यह सेवा पिछले एक साल से चल रही है। मरीजों को 25 से अधिक विशेषज्ञाओं के लिए अपॉइंटमेंट मिल रहा है। इससे समय की बचत हो रही है और इलाज जल्दी मिल रहा है। यह हेल्पलाइन सेवा आयुष्मान भारत डिजिटल हेल्थ मिशन के तहत चलाई जा रही है। टोल फो नंबर 1800238085 पर कॉल कर मरीज अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। कॉल करने पर मरीज को अपनी लोकेशन बतानी होती है। इसके आधार पर नर्जदारी अस्पतालों के विकल्प दिए जाते हैं। मरीज अपनी सुविधा के अनुसार अस्पताल और समय चुनकर अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। यह सुविधा सरकारी अस्पतालों में पहले से उपलब्ध है। अब इसे आयुष्मान भारत योजना से जुड़े निजी अस्पतालों तक भी बढ़ाया जा रहा है। इसमें 120 से अधिक अस्पताल हैं। यह सेवा सुबह 8 बजे से शाम 8 बजे तक उपलब्ध है। मरीज औपचारी समय के अनुसार अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। तथा समय पर अस्पताल जाकर डॉक्टर से परामर्श लिया जा सकता है। टोल फो नंबर पर कॉल करके मरीज अपनी आभा अर्डिंडी भी बनवा सकते हैं। इसके लिए आधार कार्ड नंबर और आधार से अधिकारी डॉ. प्रधारक तिवारी ने बताया। पुख्ता विकल्पों एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. प्रधारक तिवारी ने बताया। यह सुविधा पूरी तरह निश्चुल्क है। इससे मरीजों को बड़ी राहत मिल रही है।

## भोपाल रेल मंडल ने 1288 दिव्यांग रियायत कार्ड जारी किए

मीडिया ऑडीटर, भोपाल (एजेंसी)। भारतीय रेलवे ने दिव्यांग यात्रियों के लिए किए एवं 255 से 75 तक की छूट दी है। यह सुविधा बाधित तथा अंगीकृती हैंडिकॉप यात्रियों को मिलती है। भोपाल मंडल ने नवंबर 2023 से अब तक 1288 दिव्यांग रियायत कार्ड जारी किए हैं। भोपाल मंडल दिव्यांग सेवा की प्रभारी डॉ. ज्योति तिवारी ने बताया कि पहले सभी श्रेणियों के लिए एक ही फॉर्म का उपयोग होता था। अब रेलवे ने वर्ष 2025 से दृष्टिशील यात्रियों के लिए अलग प्रारूप (एनेक्सचर-1) और अब तीन श्रेणियों के लिए अलग प्रारूप (एनेक्सचर-2) लागू किया है। दृष्टिशील 90 या उससे अधिक यात्रियों को मिलती है। यदि दिव्यांग यात्री के साथ एक सहयोगी यात्रा करता है, तो उसे भी समान छूट मिलती है। रियायत कार्ड की जानकारी रेलवे के सॉफ्टवेयर में अपडेट होती है। इंटरक्रूजिंग के समय कार्ड की फोटो कार्पोरेट ड्रॉट ली जा सकती है।

## स्वास्थ्य विभाग में खाली पद जल्द भरें

मीडिया ऑडीटर, भोपाल (एजेंसी)। उप मुख्यमंत्री राजेन्द्र शुक्ल ने अधिकारियों से कहा है कि स्वास्थ्य विभाग में रिक्त पदों पर भर्ती का काम समय-सीमा का निर्धारण कर शीर्षता से पूरा किया जाए। आवश्यकता होने पर नियमों में आवश्यक संस्थान करने के लिए और प्रक्रिया के अनुसार अपडेट होती है। यदि दिव्यांग यात्री के साथ एक सहयोगी यात्रा करता है, तो उसे भी समान छूट मिलती है। रियायत कार्ड की जानकारी रेलवे के सॉफ्टवेयर में अपडेट होती है। इंटरक्रूजिंग के समय कार्ड की फोटो कार्पोरेट ड्रॉट ली जा सकती है।

## स्वास्थ्य विभाग में खाली पद जल्द भरें

मीडिया ऑडीटर, भोपाल (एजेंसी)। उप मुख्यमंत्री राजेन्द्र शुक्ल ने अधिकारियों से कहा है कि स्वास्थ्य विभाग में रिक्त पदों पर भर्ती का काम समय-सीमा का निर्धारण कर शीर्षता से पूरा किया जाए। आवश्यकता होने पर नियमों में आवश्यक संस्थान करने के लिए और प्रक्रिया के अनुसार अपडेट होती है। यदि दिव्यांग यात्री के साथ एक सहयोगी यात्रा करता है, तो उसे भी समान छूट मिलती है। रियायत कार्ड की जानकारी रेलवे के सॉफ्टवेयर में अपडेट होती है। इंटरक्रूजिंग के समय कार्ड की फोटो कार्पोरेट ड्रॉट ली जा सकती है।

## अक्षय तृतीय पर भोपाल में सामूहिक विवाह सम्मेलन

मीडिया ऑडीटर, भोपाल (एजेंसी)। अक्षय तृतीय पर भोपाल में सामूहिक विवाह सम्मेलन हो रहे हैं।

फैदों में 151 जोड़े विवाह सूत में बंधे।

विधायक रामेश्वर शर्मा भी बूजूर रहे।

इस दोरान सभी जोड़ों को उपहार में

श्रीरामचरित मानस दी गई। जनपद अध्यक्ष प्रमोद राजपूत ने बताया कि

मुख्यमंत्री शुक्ल ने मंगलवार को मंगलवार में यह निर्देश स्वास्थ्य, सामाजिक शृणुता विवाह आयोग के बैठक में दिए। उप मुख्यमंत्री को कहा कि आवश्यकता होने पर नियमों में आवश्यक संस्थान करने और प्रक्रिया को सरल करने के संबंध में भी प्रस्ताव तैयार करें।

## अक्षय तृतीय पर भोपाल में सामूहिक विवाह सम्मेलन

मीडिया ऑडीटर, भोपाल (एजेंसी)। अक्षय तृतीय पर भोपाल में सामूहिक विवाह सम्मेलन हो रहे हैं।

फैदों में 151 जोड़े विवाह सूत में बंधे।

विधायक रामेश्वर शर्मा भी बूजूर रहे।

इस दोरान सभी जोड़ों को उपहार में

श्रीरामचरित मानस दी गई। जनपद अध्यक्ष प्रमोद राजपूत ने बताया कि

मुख्यमंत्री शुक्ल ने मंगलवार को मंगलवार में यह निर्देश स्वास्थ्य, सामाजिक शृणुता विवाह आयोग के बैठक में दिए। उप मुख्यमंत्री को कहा कि आवश्यकता होने पर नियमों में आवश्यक संस्थान करने और प्रक्रिया को सरल करने के संबंध में भी प्रस्ताव तैयार करें।

## हर बूंद की कीमत जन सहयोग से हो रहा जल संवर्धन

मीडिया ऑडीटर, भोपाल (एजेंसी)। जल संरक्षण का

संकल्प प्रश्नान्वयी प्रारंभ किया है, जो 30 जून तक संचालित होगा।

यह अधियान जन-जन के

जीवन से जुड़ा महत्वपूर्ण अधियान है। जल गंगा संवर्धन की अधियान है। जल संरक्षण का अधियान से जल संरक्षण की अवधारणा पर आधारित है।

इस अधियान में नए जल

संग्रहण संरचनाएं बनाई

जाएंगी और पहले से मौजूद

संरचनाओं को जोड़ा जाएगा।

संक्रिया भागीदारी सुनिश्चित

करने के लिए जगरूकता

कार्यक्रम भी आयोजित किए जा रहे हैं।

अधियान समाज और सरकार की सहयोगी पहल से

एक जन अंदोलन बनता जा

रहा है।

महिला एवं बाल विकास

मंत्री श्रीमती निर्मला भूरिया

झांगुआ जिले के पेटलावद

जनपद की ग्राम पंचायत

के लिए अवधारणा तथा

उनके आवश्यकताओं को

विशेषज्ञान के लिए अवधारणा

की जाएगी।

महिला एवं बाल विकास

मंत्री श्रीमती निर्मला भूरिया

झांगुआ जिले के पेटलावद

जनपद की ग्राम पंचायत

के लिए अवधारणा

की जाएगी।

महिला एवं बाल विकास

मंत्री श्रीमती निर्मला भूरिया

झांगुआ जिले के पेटलावद

जनपद की ग्राम पंचायत

के लिए अवधारणा

की जाएगी।

महिला एवं बाल विकास

मंत्री श्रीमती निर्मला भूरिया

झांगुआ जिले के पेटलावद

जनपद की ग्राम पंचायत

के लिए अवधारणा

की जाएगी।

महिला एवं बाल विकास

मंत्री श्रीमती निर्मला भूरिया

झांगुआ जिले के पेटलावद

जनपद की ग्राम पंचायत

के लिए अवधारणा

की जाएगी।

महिला एवं बाल विकास

मंत्री श्रीमती निर्मला भूरिया

झांगुआ जिले के पेटलावद

जनपद की ग्राम पंचायत

के लिए अवधारणा



# विद्यार

# फर्जी दस्तावेजों के सहारे सरकारी खजाने को अरबों का नुकसान

केंद्रीय प्रवर्तन निदेशालय की टीम ने मध्य प्रदेश के शराब कारोबारियों से जुड़े हुए फर्जीवाड़े को लेकर 11 शराब कारोबारी के 18 ठिकानों पर छापेमारी की है। इस छापेमारी में 49 करोड़ 42 लाख रुपए की धोखाधड़ी और सरकारी खजाने में और वह रुपए की डकैती डालने का मामला सामने आया है। ईडी ने मनी लॉट्रिंग एक्ट (पीएमएलए) के तहत कार्रवाई की है। जांच एजेंसी को छापे के दौरान कई ऐसे दस्तावेज और जानकारियां प्राप्त हुई हैं, जिससे करोड़ों-अरबों रुपए का किया गया घोटाला मध्य प्रदेश में उजागर हुआ है। मध्य प्रदेश में 2015-16 में पहली बार यह मामला उजागर हुआ था। उस समय इस मामले को दबा दिया गया था। हाल ही में ईडी की टीम ने जब छापा मारकर जांच शुरू की। उसके बाद एक के बाद एक नए फर्जीवाड़े की परतें खुलकर सामने आनी शुरू हो गई हैं। 2015-16 से 2017-18 के बीच चालानों में फर्जीवाड़ा किया गया। जिससे सरकार को अरबों रुपए का नुकसान उठाना पड़ा। बैंक गारंटी के रूप में फर्जी गारंटी प्रस्तुत की गई। शराब कारोबारियों द्वारा दस्तावेजों में हेराफेरी करके करोड़ों रुपए का नुकसान सरकारी खजाने को पहुंचाया गया। सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों की मिलीभगत से शराब कारोबारी फर्जीवाड़ा कर रहे थे। इस लूट में सभी शामिल थे। जब मामला सामने आया, तब तत्कालीन आबकारी मंत्री की भूमिका संदेहासप्रद रही। आबकारी विभाग के जिस अधिकारी संजीव दुबे की सरपरस्ती में आबकारी विभाग में करोड़ों रुपए के घोटाले हुए थे, 2017 में उसकी एफआईआर दर्ज हुई। क्योंकि इस लूट में आबकारी विभाग के महत्वपूर्ण पदों में बैठे लाग शामिल थे अतः मामले को दबा दिया गया। जब यह मामला उजागर हुआ, तब शराब ठेकेदारों ने 22 करोड़ रुपए सरकार के खाते में जमाकर मामले को दबबा दिया था। इस मामले को दबाने में आबकारी विभाग के अधिकारी और तत्कालीन मंत्री की भूमिका थी। उस समय सभी जिम्मेदार पदों पर बैठे हुए पदाधिकारियों ने इस लूट में अपना-अपना हिस्सा वसूल किया था। 2017 से यह मामला ईडी के पास लंबित पड़ा हुआ था। केंद्रीय प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारियों द्वारा बार-बार जानकारी मांगी गई। उसके बाद भी आबकारी विभाग द्वारा ईडी को समय पर जानकारी नहीं दी जा रही थी। ईडी ने शराब कारोबार से जुड़े ठेकेदारों और अधिकारियों की जांच अपने स्तर पर कर 18 ठिकानों पर छापेमारी की है। अभी तक लगभग 50 करोड़ रुपए के सरकारी राजस्व को नुकसान पहुंचाने वाले दस्तावेजों को ईडी ने जम किया है। इस मामले की जिस तरह से ईडी जांच कर रही है, उससे अरबों रुपए की धोखाधड़ी के नए मामले उजागर होने की संभावना ईडी के अधिकारियों ने व्यक्त की है। शराब कारोबारियों और आबकारी विभाग के अधिकारियों तथा राजनेताओं की मिली भगत से बड़े पैमाने पर अरबों रुपए के घोटाले हर राज्य में हो रहे हैं।

# न्यायिक नियुक्ति आयोग के खात्मे का दर्द नहीं भूली केंद्र सरकार

सुप्रीम कोर्ट केंद्र सरकार की इस मंशा को भाप गया था। वर्ष 2015 में दिए गए फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने आयोग को असंवैधानिक बताते हुए निरस्त कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जजों की नियुक्ति में न्यायपालिका की स्वतंत्रता को बनाए रखना महत्वपूर्ण है और न्यायिक आयोग इस स्वतंत्रता को खतरे में डालता है।

राज्यपाल और राष्ट्रपति के बिल रोकने के मामले में सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों से केंद्र सरकार से उत्पन्न टकराहट की जड़ में न्यायिक नियुक्ति आयोग पर दिया गया फैसला है। सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति को लेकर केंद्र सरकार द्वारा संसद में पारित किए गए न्यायिक नियुक्ति आयोग को निरस्त करते हुए सुप्रीम कोर्ट की कॉलेजियम व्यवस्था को जारी रखा था। इस आयोग के जरिए केंद्र सरकार चाहती थी कि न्यायाधीशों की नियुक्ति में उसकी भी भूमिका होनी चाहिए। अकेले सुप्रीम कोर्ट को यह हक नहीं होना चाहिए कि अपने चहते न्यायाधीशों की नियुक्ति करे।

सुप्रीम कोर्ट केंद्र सरकार की इस मंशा को भाप गया था। वर्ष 2015 में दिए गए फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने आयोग को असंवैधानिक बताते हुए निरस्त कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जजों की नियुक्ति में न्यायपालिका की स्वतंत्रता को बनाए रखना महत्वपूर्ण है और न्यायिक आयोग इस स्वतंत्रता को खतरे में डालता है। इस फैसले पर भी खूब वाद-विवाद हुआ था। न्यायिक आयोग के जरिए केंद्र सरकार पर सुप्रीम कोर्ट में दखलांदाजी करने और इसे राजनीतिक अखाड़ा बनाने की बात कही गई थी। दूसरी तरफ न्यायिक आयोग की पैरवी करने वाले केंद्र सरकार के पैरवीकारों का कहना था कि न्यायाधीशों की नियुक्ति में भाई-भतीजावाद हावी है। आयोग के निरस्त होने का रंज केंद्र सरकार को अभी तक है। इसी वजह से राज्यपाल और राष्ट्रपति के बिल रोकने के मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले से केंद्र सरकार से छत्तीस का आंकड़ा बन गया है। तमिलनाडु बनाम राज्यपाल मामले में सुप्रीम कोर्ट ने राज्यपाल की तरह राष्ट्रपति के लिए भी दी

सुप्रीम कोर्ट केंद्र सरकार की इस मंशा को भाप गया था। वर्ष 2015 में दिए गए फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने आयोग को असवैधानिक बताते हुए निरस्त कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जजों की नियुक्ति में न्यायपालिका की स्वतंत्रता को बनाए रखना महत्वपूर्ण है और न्यायिक आयोग इस स्वतंत्रता को खतरे में डालता है। इस फैसले पर भी खूब वाद-विवाद हुआ था। न्यायिक आयोग के जरिए केंद्र सरकार पर सुप्रीम कोर्ट में दखलांदाजी करने और इसे राजनीतिक अखाड़ा बनाने की बात कही गई थी। दूसरी तरफ न्यायिक आयोग की पैरवी करने वाले केंद्र सरकार के पैरवीकारों का कहना था कि न्यायाधीशों की नियुक्ति में भाई-भतीजावाद हावी है। आयोग के निरस्त होने का रंज केंद्र सरकार को अभी तक है। इसी वजह से राज्यपाल और राष्ट्रपति के बिल रोकने के मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले से केंद्र सरकार से छत्तीस का आंकड़ा बन गया है। तमिलनाडु बनाम राज्यपाल मामले में सुप्रीम कोर्ट ने राज्यपाल की तरह राष्ट्रपति के लिए भी दी



यह भी अपेक्षित है कि वे सहयोगात्मक बनें तथा उठाए जाने वाले प्रश्नों के उत्तर देकर सहयोग प्रदान करें तथा केंद्र सरकार द्वारा दिए गए सुझावों पर शीघ्रता से विचार करें। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद राजनीतिक बवंडर आ गया। उप राष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले को लेकर न्यायपालिका के बारे में सख्त टिप्पणी कर दी। उन्होंने कहा कि अदालतें राष्ट्रपति को आदेश नहीं दे सकतीं। उप राष्ट्रपति ने इसकी ओर इशारा करते हुए कहा कि संविधान का अनुच्छेद 142 एक ऐसा परमाणु मिसाइल बन गया है जो लोकतांत्रिक ताकतों के खिलाफ न्यायपालिका के पास चौबीसों घंटे मौजूद

रहता है। उन्होंने कहा कि देश में ऐसी स्थिति नहीं हो सकती कि आप राष्ट्रपति को निर्देश दें। सुप्रीम कोर्ट को ये अधिकार किसने दिया है और वो किस आधार पर ऐसा कर सकता है।

गौरतलब है कि संविधान का अनुच्छेद 142 सुप्रीम कोर्ट को ये अधिकार देता है कि वो पूर्ण न्याय करने के लिए कोई भी आदेश, निर्देश या फैसला दे सकता है चाहे वो किसी भी मामले में क्यों न हो। लेकिन उप राष्ट्रपति ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट सिफर संविधान की व्याख्या कर सकता है। धनंजय डड़ने ने कहा कि हमारे पास ऐसे जज हैं जो अब कानून बनाएंगे, कार्यपालिका का

काम करेंगे और एक सुपर संसद की तरह भी काम करेंगे और कोई जिम्मेदारी नहीं लेंगे, क्योंकि इस देश का कानून उन पर लागू तो होता नहीं। उपराष्ट्रपति ने हाई कोर्ट के जज यशवंत वर्मा के दिल्ली आवास से कथित तौर पर जले नोट मिलने के बाद भी एफआईआर दर्ज न होने पर सवाल उठाया।

उन्होंने कहा कि ये घटना किसी आम आदमी के घर में होती तो बैजली की गति से कार्रवाई होती। लेकिन यहाँ तो बैलगाड़ी की रफ़तार से भी कार्रवाई नहीं हो रही है। उन्होंने कहा कि विधानसभा का चुनाव हो या लोकसभा का हर सांसद, विधायक और उम्मीदवार को अपनी संपत्ति घोषित करनी होती है लेकिन वे (जज) ऐसा कुछ नहीं करते।

इस पर पलटवार करते हुए डीएमके राज्यसभा सांसद तिरुचि शिवा ने कहा कि संविधान की रक्षा करने का अधिकारी होने से किसी व्यक्ति को ये अधिकार नहीं मिल जाता कि वो संसद में पारित विधेयकों को अनिश्चित काल तक रोक कर रख सकता है। सीपीआई नेता डी राजा ने कहा कि लोकतांत्रिक ढाँचे को बचाए रखने लिए चेक एंड बैलेंस जरूरी है। संविधान का अनुच्छेद 74(1) यह साफ कहता है कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह से बंधे हैं। राष्ट्रपति सर्वोच्च संवैधानिक पद पर रहते हुए, ऐसे मामलों में स्वतंत्र विवेक का इस्तेमाल नहीं करते। उन्होंने कहा कि उपराष्ट्रपति की टिप्पणी आरएस-भाजपा की ओर से अगर कार्यपालिका अपना काम नहीं कर रही है, तो न्यायपालिका को हस्तक्षेप करना चाहिए। ऐसा करना उनका अधिकार है। उन्होंने कटाक्ष करते हुए कहा कि न्यूक्लियर मिसाइल तो नोटबंदी थी, तब किसी को तकलीफ नहीं हुई? दरअसल सत्तारूढ़ राजनीतिक दलों के राजनीतिक उद्देश्य होते हैं, जब ये संविधान के दायरे में पूरा नहीं होते तब अदालतों से टकराहट की नौबत आती है। इसकी पुनरावृत्ति निश्चित तौर पर लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए घातक है ऐसे विवादस्पद मुद्दों को सभी पक्षों को मिलबैठ कर निपटाने से ही देश की संवैधानिक विविधता और एकता-अखंडता मजबूत रहेगी।

# किसान उत्पादक संगठन का बढ़ता कारबां

साल 2014 के आम चुनावों के बत्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुआई वाली भारतीय जनता पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में साल 2022 तक भारतीय किसानों की आय दोगुना करने का वादा किया था। भारतीय कृषि की चुनौतियों को देखते हुए इस लक्ष्य को हासिल करना असान नहीं। भारतीय किसान मोहन वाले खबर कहता है क्लेक्चर

आसान नहीं। भारतीय किसान मेहनत तो खूब करता है, लेकिन आधुनिकीकरण की कमी, मांग और स्थान के लिहाज से व्यवस्थित आपूर्ति प्रबंधन की कमी और कृषि जोत में लगातार कमी के चलते उसे उसके परिश्रम का वाजिब फल नहीं मिल पाता। इन्हीं समस्याओं को देखते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने किसान उत्पादक संगठन की परिकल्पना की, इसके अंग्रेजी शब्दों के पहले अक्षर के नाम पर इसे एफपीओ के नाम से भी जाना जाता है। इस परिकल्पना को प्रधानमंत्री मोदी ने 29 फरवरी 2020 को मूर्त रूप दिया। इस योजना की सफलता का अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इसे लागू होने के ठीक पांच साल बाद यानी 24 फरवरी 2025 को बिहार के भागलपुर में प्रधानमंत्री ने दस हजारवें एफपीओ की शुरूआत की। बिहार के खगड़िया जिले में पंजीकृत इस एफपीओ का मकसद मवका, केला और धान की फसल के उत्पादन और उसके विपणन पर है।



बहरहाल एफपीओ योजना के तहत साल 2027-28 तक के लिए सरकार ने छह हजार 865 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। इनकी मदद से एफपीओ को वित्तीय संसाधन मुहैया हुआ। इक्की बजह से आज एफपीओ ना सिर्फ किसान संगठन हैं, बल्कि किसानों की आय बढ़ाने और छोटे किसानों को अहम बाजार लाभ, मोल-भाव की ताकत और बाजार तक पहुंच में सुधार की दिशा में सीधी पहुंच मुहैया कराने वाला मंच बन चुका है। इस मंच ने किसानों को सामूहिक सौदेबाजी की ताकत दी है। अब तक के उपलब्ध आंकड़ों के हिसाब से देखें तो देश के पंजीकृत एफपीओ में करीब 30 लाख किसान सीधे जुड़े हुए हैं। जिनमें करीब 40 प्रतिशत महिलाएं हैं। सरकारी समर्थन, बाजार तक सीधी पहुंच और सहकारी प्रयास की वजह से ये एफपीओ कृषि क्षेत्र में अब हजारों करोड़ रुपये का ना सिर्फ सीधे कारोबार कर रहे हैं, बल्कि किसानों की समृद्धि बढ़ाने में भी सहयोगी बने हुए हैं।

के तहत पंजीकृत किसान-उत्पादक संगठन हैं। खेती-किसानी और उससे जुड़ी गतिविधियों और उत्पादन के साथ ही विपणन से फायदा उठाने की कोशिश के तहत इन संगठनों को खड़ा किया गया है। एकपीओ के सदस्य किसान होते हैं, इस लिहाज से कह सकते हैं कि एकपीओ एक तरह से किसान-सदस्य द्वारा नियंत्रित उनका अपना स्वैच्छिक संगठन है। इसके सदस्य इसकी नीतियों के निर्माण और उन पर फैसला लेने में सक्रिय भूमिका निभाते हैं। इनकी सदस्यता के लिए लिंग, समाज नस्ल, राजनीतिक या धार्मिक विचार आदि का ध्यान नहीं रखा जाता। इन सदस्यता उन सभी लोगों को मिल सकती है, जो इसकी सेवाओं का उपयोग तो कर ही सकते हैं, सदस्यता के जिम्मेदारी को स्वीकार कर सकते हैं। एकपीओ के संचालक अपने किसान-सदस्यों, निर्वाचित प्रतिनिधियों, प्रबंधकों एवं कर्मचारियों को जरूरी शिक्षा और प्रशिक्षण मुहैया कराते हैं ताकि वे अपने संगठन के विकास में प्रभावी भूमिका निभाएं। सहकारी आंदोलन प्रभावी राज्यों मसलन, गुजरात महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान आदि में इन्होंने बेहतु उत्साहजनक नीति दिखाए हैं।

इस आदालत में महिलाओं को भागादारों जबरदस्त तरीके से बढ़ रही है। साल 2024 के अंकड़े के अनुसार, इस साल तक रंजिस्टर्ड हुए 810 एफपीओ ऐसे रहे, जिनकी प्रत्येक सदस्य सिर्फ महिलाएँ हैं। बहरहाल एफपीओ के जरिए किसान अपनी उपज के बदले बेहतर कमाई कर पा रहे हैं। राजस्थान के पाली ज़िले की आदिवासी महिलाओं ने एक उत्पादक कंपनी का गठन किया और इसके माध्यम से उन्हें शरीफा/कर्स्टर्ड एप्पले के उच्च मूल्य प्राप्त हो रहे हैं।

इन संगठनों के गठन के पीछे की अवधारणा बुनियादी रूप से किसानों के कल्याण पर केंद्रित है। इसके जरिए कृषि उत्पाद तैयार करने वाले किसान अपने लिए समूह बना सकें। शुरू में ही दस संगठनों के गठन का असल मकसद, स्थायी आमदनी केंद्रित खेती-किसान और उत्पादन को बढ़ावा देना और किसानों की आय बढ़ाना है। इस योजना पर साल 2027-28 तक छह हजार 865 करोड़ रुपए के साथ शुरू किया गया था।

सरकार इस योजना को सफलता को लेकर कितना सज़ोदा है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इस योजना के तहत गठित हर नए एफपीओ को पांच साल तक हैंडहोल्डिंग समर्थन के साथ ही उन्हें तीन साल तक प्रबंधन खर्च के लिए 18 लाख रुपये की वित्तीय सहायता दी जा रही है। इसके साथ ही एफपीओ के प्रत्येक सदस्य किसान को दो हजार रुपए का प्रतिभूति अनुदान दिया जाएगा। जिसकी सीमा प्रति एफपीओ 15 लाख रुपये होगी। इसके साथ ही उन्हें संस्थागत ऋण सुनिश्चित करने के लिए हर एफपीओ को दो करोड़ रुपये तक के परियोजना ऋण की गारंटी सुविधा दी जा रही है।

भारतीय किसानों का सबसे बड़ा समस्या उनको पेदावार को सही जगह और खरीदार तक पहुंचाने के लिए व्यवस्थित प्रबंधन की कमी है। इसके साथ ही भारतीय खेती की जोत लगातार कम होती चली गई है। देश में औसत जोत का आकार साल 1970-71 में जहां 2.3 हेक्टेयर था, वह साल 2015-16 में घटकर महज 1.08 हेक्टेयर रह गया। इसी तरह खेती में छोटे और सीमात किसानों की हिस्सेदारी साल 1980-81 के 70 प्रतिशत की तुलना बढ़कर साल 2015-16 में 86 फीसद हो गई। दरअसल घटती जोत और बढ़ती किसान हिस्सेदारी के चलते किसानों की आय या तो बढ़ नहीं रही या फिर घट रही है। ऐसे में एफपीओ किसानों के लिए बरदान बन कर सामने आए हैं। अब एफपीओ खेती की उपज, उनके बेहतर विपणन और सही जगह पर पहुंच के साथ ही खेती में नवाचार और विकास की दिशा में सहयोगी रूख अपना रहे हैं। इसका असर है कि एफपीओ के जरिए जहां खेती की उपज बढ़ रही है, वहां किसान वैकल्पिक उपजों के सहरे अपनी आय को बढ़ा रहा है। एफपीओ छोटे, सीमात और भूमिहीन किसानों को खेती के दौरान उहें प्रौद्योगिकी, गुणवत्तायुक्त बीज, खाद और कीटनाशकों की पहुंच सुनिश्चित करा रहा है। जहां जरूरत होती है, वहां के लिए जरूरी वित्तीय सहयोग भी एफपीओ किसानों को मुहैया करा रहा है। इसके जरिए छोटे, सीमात और भूमिहीन किसान सामूहिक रूप से संगठित हो रहे हैं। एफपीओ खेती की उपज के प्रबंधन, उसमें तकनीक को बढ़ावा देने में भी सहयोगी और प्रभावी भूमिका निभा रहे हैं।

भारतीय कृषि क्षेत्र में एफपीओ किस तरह अहम भूमिका निभा रहे हैं, इसे समझने के लिए इसे मिलने वाली सहायिताओं की तरफ देखना होगा। एफपीओ को इनपुट जुटाने के लिए कार्यशील पूँजी, विपणन और अपने सदस्य किसानों को बेहतर सेवाएं मुहैया कराने के लिए अनुदान और ऋण दोनों तरह की आधिक सहायता दे रहे हैं। एफपीओ को जरूरत पर धन मिल सके, इसके लिए वित्तीय संस्थानों से ऋण के मद में केंद्रीय योजना के तहत ऋण गारंटी निधि का प्रावधान किया गया है। इसके साथ ही देश भर के उपभोक्ताओं को ऑनलाइन उपज बेचने के लिए आठ हजार पंजीकृत किसान उत्पादक संगठनों में से लगभग पांच हजार को ऑपन नेटवर्क फॉर डिजिटल

में से लगभग पाँच हजार का आपने नटवक कार डिजिटल कॉमर्स यानी ओएनडीसी पोर्टल पर पंजीकृत किया गया है। एफपीओ के जरिए किसानों को जहां सामूहिक सौदेबाजी की ताकत बढ़ी है, वहीं उन्हें वित्तीय सहयोग मिल रहा है। इस वित्तीय सहयोग से उन्हें वक्त पर तकनीकी सहयोग, जरूरी खाद और कीटनाशक मिल रहा है। इसके साथ ही उन्हें अपनी उपज को खरीदारों तक सीधे पहुंचाने की भी ताक दी है। इस ताकत के चलते किसानों की समृद्धि बढ़ रही है। उम्मीद की जा रही है कि एफपीओ का कारबां अगर इसी तरह बढ़ता रहा तो वह दिन दूर नहीं, जब भारत के किसान समाज के दूसरे नौकरीपेशा और कारोबारी लोगों की तरह समृद्ध और सहज जीवन जीने के कालिल होंगे। बशर्ते कि एफपीओ का यह कारबां यूं बढ़ता रहे।







